

मसौदा परिपत्र पर प्राप्त फीडबैक पर विवरण

विषय: ओटीसी डेरिवेटिव लेनदेन के लिए विशिष्ट लेनदेन अभिज्ञापक

1. परिपत्र : दायरा

मसौदा परिपत्र का पैरा 2 : रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव, सरकारी प्रतिभूतियों में वायदा संविदा, विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव, विदेशी मुद्रा ब्याज दर डेरिवेटिव और ऋण डेरिवेटिव के लिए ओटीसी बाजारों में सभी लेनदेन के लिए यूटीआई को लागू करने का निर्णय लिया गया है।

फीडबैक : यूटीआई कार्यान्वयन के दायरे पर स्पष्टता मांगी गई, जिसमें बाजार निर्माता के संबंधित पक्षों द्वारा किए गए डेरिवेटिव लेनदेन के लिए प्रयोज्यता भी शामिल है।

आरबीआई की टिप्पणियाँ : इस पर विचार नहीं किया गया क्योंकि यह पहले से ही कवर किया गया है। निदेशों के पैरा 2 और निदेशों के अनुबंध के पैरा 2 में निर्धारित शासी निदेशों के अनुसार निदेशों का दायरा ओटीसी डेरिवेटिव बाजारों में किए गए लेनदेन तक विस्तारित है।

2. परिपत्र : कार्यान्वयन के लिए समयसीमा

मसौदा परिपत्र का पैरा 3 : अनुदेश 01 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे।

फीडबैक : रिपोर्टिंग प्रारूप और परिचालन दिशानिर्देश जारी करने के बाद आवश्यकताओं को लागू करने के लिए पर्याप्त अवधि प्रदान करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ।

आरबीआई टिप्पणियाँ : स्वीकृत। यूटीआई के कार्यान्वयन की समयसीमा को संशोधित कर 01 जनवरी, 2027 कर दिया गया है, जिससे बाजार सहभागियों को आवश्यक तकनीकी क्षमताओं के निर्माण के लिए पर्याप्त समय मिल सके। यह निदेशों के पैरा 3 में दर्शाया गया है।

3. अनुबंध : बकाया ट्रेडों के लिए यूटीआई

मसौदा परिपत्र का अनुबंध पैरा 2.1 : शासी निदेशों के अनुसार ओटीसी डेरिवेटिव बाजार में किए गए सभी लेनदेन के लिए यूटीआई अनिवार्य रूप से सृजित/रिपोर्ट किया जाएगा।

फीडबैक : इस बात पर स्पष्टता मांगी गई कि क्या यूटीआई वैसे ओटीसी डेरिवेटिव ट्रेडों पर लागू होगा जो निदेश लागू होने की तारीख पर बकाया रहेंगे।

आरबीआई टिप्पणियाँ : स्वीकृत। ये निदेश, निदेशों के प्रभावी होने की तारीख को या उसके बाद किए गए ओटीसी डेरिवेटिव लेनदेन पर लागू होंगे। यह निदेशों के पैरा 3 और निदेशों के अनुबंध के पैरा 2 में दर्शाया गया है।

4. अनुबंध : यूटीआई सृजक इकाई

मसौदा परिपत्र का अनुबंध पैरा 3.2 : यूटीआई सृजक इकाई का निर्धारण सारणी 1 में दिए गए प्रवाह (वाटरफॉल) के अनुसार किया जाएगा, जिसमें यूटीआई सृजन की जिम्मेदारी प्रवाह में अगली इकाई

को सौंप दी जाएगी, यदि अभिज्ञापित यूटीआई सृजक इकाई यूटीआई सृजन करने में असमर्थ या अनिच्छुक है।

फीडबैक : यूटीआई सृजन करने के लिए ईटीपी को अधिकार देने का सुझाव दिया गया। एक इकाई ने इस बारे में स्पष्टता मांगी कि क्या यूटीआई एक वेंडर द्वारा स्वीकार किया जा सकता है।

आरबीआई टिप्पणियाँ : अस्वीकृत। निदेशों में क्रम निर्धारित करते हुए एक प्रवाह (वाटरफॉल) निर्धारित किया गया है और यूटीआई सृजन करने में सक्षम/इच्छुक इकाइयों से ऐसा करने की अपेक्षा की जाती है। वैश्विक मानकों के अनुरूप, यह अधिदेश यूटीआई के सृजन/रिपोर्टिंग के लिए है, जिसमें उस विशिष्ट इकाई के संबंध में लचीलापन प्रदान किया गया है जो यूटीआई सृजन करेगी। किसी वेंडर को यूटीआई सृजन के प्रत्यायोजन, जहां यूटीआई में शामिल एलईआई वेंडर का होगा, की अनुमति नहीं है।

5. अनुबंध : सारणी 1 : यूटीआई का सृजन

अनुबंध सारणी 1. बी. मसौदा परिपत्र का पैरा 4 : अनेक क्षेत्राधिकारों में रिपोर्ट करने योग्य लेनदेन के लिए, जहां विदेशी क्षेत्राधिकार में शीघ्रतर रिपोर्टिंग समयरेखा नहीं है, यूटीआई को प्रतिपक्षकारों के बीच सहमति के आधार पर पहचानी गई इकाई के अनुसार सृजित किया जा सकता है कि यूटीआई किसे सृजित करना चाहिए।

ए) फीडबैक : यूटीआई सृजन करने वाली इकाई पर सहमति की प्रणाली और दस्तावेजों के प्रारूप पर स्पष्टता मांगी गई।

आरबीआई टिप्पणियाँ : आंशिक रूप से स्वीकृत। बाजार सहभागियों को स्पष्टता और लचीलापन प्रदान करने के लिए, निदेशों को संशोधित किया गया है ताकि यह इंगित किया जा सके कि यूटीआई सृजन करने वाली इकाई पर प्रतिपक्षकारों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमति बनाई जा सकती है। केवल भारत में रिपोर्ट करने योग्य लेनदेन के लिए भी इसी तरह के प्रावधान को शामिल किया गया है।

बी) फीडबैक : रिपोर्टिंग इकाइयों द्वारा यूटीआई सृजन के लिए अनुरोध और एलईआई सॉर्टिंग के आधार पर यूटीआई सृजक प्रतिपक्षकार का निर्धारण।

आरबीआई की टिप्पणियाँ : इस पर विचार नहीं किया गया क्योंकि यह पहले से ही कवर किया गया है। ये निदेश प्रतिपक्षकारों को यूटीआई सृजक इकाई पर पारस्परिक रूप से सहमत होने में सक्षम बनाते हैं। इस प्रावधान का उपयोग प्रतिपक्षकारों द्वारा यूटीआई सृजन करने वाली इकाई को निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है, जिसमें एलईआई सॉर्टिंग भी शामिल है।

6. अनुबंध : अंतरिम यूटीआई

मसौदा परिपत्र का अनुबंध पैरा 3.3 : यदि बाजार प्रतिभागी रिपोर्टिंग समय सीमा के भीतर यूटीआई की रिपोर्ट करने में असमर्थ है, तो बाजार प्रतिभागी लेनदेन की तारीख से दो कारोबार दिवसों के भीतर यूटीआई प्राप्त कर सकता है और सीसीआईएल-टीआर को प्रस्तुत कर सकता है। सीसीआईएल-टीआर द्वारा पूर्व में सृजित यूटीआई को तब एक अस्थायी/अंतरिम यूटीआई के रूप में माना जाएगा।

ए) फीडबैक : अंतिम यूटीआई प्रस्तुत करने की समयसीमा को लेनदेन की तारीख से पांच कारोबार दिवसों तक बढ़ाने का अनुरोध।

आरबीआई टिप्पणियाँ : स्वीकृत। यूटीआई के कार्यान्वयन के लिए वैश्विक दृष्टिकोणों के आकलन के आधार पर, बाजार सहभागियों को यूटीआई की रिपोर्ट करने के लिए लेनदेन की तारीख से पांच कारोबार दिवस प्रदान किए गए हैं। निदेशों के अनुबंध के पैरा 5 में आवश्यक परिवर्तनों को शामिल किया गया है।

बी) फीडबैक : रिपोर्टिंग प्रतिपक्षकार के लिए अस्थायी यूटीआई सृजन करने और सीसीआईएल-टीआर को रिपोर्ट करने के लिए प्रावधान का अनुरोध।

आरबीआई टिप्पणियाँ : स्वीकृत। सीसीआईएल-टीआर को लेनदेन की रिपोर्ट करते समय प्रतिपक्षकार से यूटीआई उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, बाजार सहभागियों को अस्थायी यूटीआई की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए एक प्रावधान जोड़ा गया है। निदेशों के अनुबंध के पैरा 5 में आवश्यक परिवर्तनों को शामिल किया गया है।

7. अनुबंध : रिपोर्टिंग प्रारूप

मसौदा परिपत्र का अनुबंध पैरा 3.5 : सीसीआईएल, संशोधन या परिशोधन सहित ओटीसी डेरिवेटिव लेनदेन की यूटीआई के साथ रिपोर्टिंग के लिए, संशोधित रिपोर्टिंग प्रारूप जारी करेगा, जिसमें इस उद्देश्य के लिए परिचालन दिशानिर्देश शामिल हैं।

फीडबैक : व्यापक दिशानिर्देश और रिपोर्टिंग प्रारूप, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न आदि प्रदान करने का अनुरोध; नवाचार, पोर्टफोलियो संपीड़न, संशोधन, समाप्ति, उपयोग, आंशिक रद्दीकरण, आदि के आधार पर ट्रेडों की रिपोर्टिंग पर विभिन्न परिचालनगत पहलुओं पर स्पष्टता प्रदान करने के लिए कुछ अनुरोध; यूटीआई को बाजार सहभागियों के साथ साझा करने के तरीके आदि के बारे में स्पष्टता मांगी गई।

आरबीआई की टिप्पणियाँ : इस पर विचार नहीं किया गया क्योंकि यह पहले से ही कवर किया गया है। निदेशों के अनुबंध के पैरा 7 में इंगित किया गया है कि सीसीआईएल, ओटीसी डेरिवेटिव लेनदेन की यूटीआई के साथ रिपोर्टिंग के लिए संशोधित रिपोर्टिंग प्रारूप और इस उद्देश्य के लिए परिचालन दिशानिर्देश जारी करेगा। प्रारूपों/दिशानिर्देशों में उपयुक्त समावेश करने के लिए सीसीआईएल के साथ इन प्रश्नों/अनुरोधों को साझा किया गया है।